भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.5856

(जिसका उत्तर सोमवार, 30 मार्च, 2026/09 चैत्र 1948 (शक) को दिया जाना है)

राजकोषीय घाटा

5856. श्री सौमेंदु अधिकारी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य प्राप्त लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए प्रस्तावित धनराशि और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में सरकार का राजकोषीय घाटा कितना है; और
(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राजकोषीय समेकन के मार्ग को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ताकि घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से नीचे लाया जा सके और वर्ष 2035 तक ऋण-जीडीपी अनुपात को वर्तमान 56.1 प्रतिशत से 50+1 प्रतिशत तक पहुंचया जा सके?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख) सरकार का राजकोषीय घाटा 2020-21 में जीडीपी के 9.2% से घटकर 2024-25 में जीडीपी के 4.8% पर आ गया है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटे (एफडी**)** का विवरण–राशि के रूप में और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में–नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपये में)	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में एफडी
2020-21	18,18,291	9.2
2021-22	15,84,521	6.7
2022-23	17,37,755	6.5
2023-24	16,54,643	5.5
2024-25	15,74,431	4.8

पुनर्वितीय बजट 2025-26 और बजटीय बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹15,58,492 करोड़ (जीडीपी का 4.4 प्रतिशत) और ₹16,95,768 करोड़ (जीडीपी का 4.3 प्रतिशत) रखा गया है।

(ग) संभावित विकास रुझानों और उभरती विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पिछले बजटों में घोषित राजकोषीय घाटे और ऋण समेकन के लक्ष्यों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रभावी पूंजीगत व्यय पर विशेष ध्यान दिया जाना शामिल है। उदाहरण के लिए, बजट अनुमान 2026-27 में सरकार के ऋण (₹16.96 लाख करोड़) का उपयोग ₹17.15 लाख करोड़ के प्रभावी पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

*****